







# विचार

## सैफ अली खान पर हमले के बाद महाराष्ट्र में सियासत गरमाई

सड़क दुर्घटनाओं पर काबू न पाए जा सकने को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री की चिंता वाजिब है। इसके लिए वे खराब सड़क निर्माण को जिम्मेदार मानते हैं। संसद में भी उन्होंने कहा था कि विदेश में जब भी भारत में सड़क दुर्घटनाओं और सड़कों के निर्माण को लेकर बात होती है, तो उन्हें शर्म से मुँह छिपाना पड़ता है। अभी भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। इसका बड़ा कारण सड़कों का खराब होना से निर्माण किया जाना है।

उन्होंने कहा कि खराब सड़क निर्माण को गैर-जमानती अपराध बना दिया जाना चाहिए। सड़क निर्माण के ठेकेदारों और इंजीनियरों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। निस्संदेह यह सुझाव कठोर लग सकता है। मगर चूंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने संकल्प लिया है कि वह 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को घटा कर आधा कर देगा, बिना ऐसे कठोर कदम उठाए उसका लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं होगा। मंत्रालय के अनुसार 2023 में पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें से एक लाख बहतर हजार लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक लाख चौदह हजार लोगों की उम्र अठारह से पैंतालीस वर्ष के बीच थी। सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए कई उपाय आजमाए जा चुके हैं। यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया। जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मगर इसका कोई उल्लेखनीय असर नजर नहीं आया। सड़क दुर्घटनाएं हर वर्ष कुछ बढ़ी हुई ही दर्ज होती हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मौत का सबसे बड़ा कारण सड़कों का खराब ढंग से निर्माण चिह्नित किया गया है। राजमार्गों और द्रुतगामी सड़कों पर चौड़ाई आदि में एकरूपता और मोड़ों पर उचित तकनीक का इस्तेमाल न होने के कारण दुर्घटनाएं और मौतें अधिक होती हैं।

अच्छी बात है कि परिवहन मंत्री ने इस बात की पहचान की और इसे स्वीकार भी किया। सड़कों पर जिन वजहों से दुर्घटनाएं और मौतें होती हैं, उन्हें दूर करने के लिए भारी रकम भी आबंटित की गई है।

# मेटा की माफी से सोशल मीडिया मंचों को सख्त सन्देश

# लिलित गर्ग

फेसबुक के लिये भारत एक संभावनाओं भरा बड़ा बाजार होने के बावजूद उसकी भारत के प्रति सोच भ्रामक, विवादास्पद एवं नकारात्मक रही है। फेसबुक और मेटा भारत के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ और फेकन्यूज़ को लेकर विवादों में घिरती रही हैं। हाल ही में मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग एक बार फिर भारत को लेकर दिये गलत बयान के मामले में फँस गए हैं। ज़करबर्ग ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि कोरोना के बाद दुनिया के कई देशों में मौजूदा सरकारें गिर गईं। भारत के लोकसभा चुनाव में भी नरेन्द्र मोदी सरकार हार गई। यह जनता का सरकारों में घटता भरोसा दिखाता है।

शामिल हुए थे। तभी उन्होंने रिलायंस के साथ इसको लेकर एक समझौता किया था। इस तरह मेटा के लिए भारत अहम है, तो इसके मालिक को भारत का नाम बहुत संभलकर एवं सोच समझकर लेना चाहिए। वैसे भी भारत सरकार अमेरिका, यूरोपीय देशों या चीन की तरह आक्रामक एवं उग्र नहीं है। आक्रामक देशों में तो सरकारें फेसबुक या मेटा की गलतियों पर उसे न केवल सबक सीखाती है बल्कि कई बार ऐसी गलतियों के चलते कंपनियों को भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ता है। उन देशों की कड़ाई का ही नतीजा है कि सोशल मीडिया कंपनियां इन देशों में बहुत सजग रहती हैं, जबकि भारत के मामले में उनकी नीति बदल जाती है। भारत की उदारता का ये कंपनियां अधिकतम दुरुपयोग करना चाहती हैं। भारत को भी उदारता, सरलता एवं लचीलेपन की जगह कठोर एवं सख्त रखवाया अपनाना चाहिए क्योंकि भारत अब दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने के साथ दुनिया में अपनी एक स्वतंत्र एवं ठोस जगह बना चुका है। जुकरबर्ग से जुड़ा यह ताजा मामला ऐसे ही लोगों के लिये एक सबक एवं चेतावनी बनना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि वह ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिकों और अधिकारियों को चेतावनी के शब्दों में सचेत कर दे कि वे भारत के महत्व को समझें, पर्याप्त सजग एवं सावधान रहें। भारतीयों को पता है कि साल 2019 में अमेरिका में फेडरल ट्रेड कमीशन ने उपयोगकर्ता की गोपनीयता का उल्घंघन करने के लिए फेसबुक पर पांच अरब डॉलर का जर्माना लगाया था।



इस बयान के बाद संसद की आईटी एंड कम्प्युनिकेशन मामलों की स्टैंडिंग कमिटी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि इस गलत बयान पर कंपनी को माफी मांगनी चाहिए। वरना हमारी समिति उन्हें मानवानि का नोटिस भेजेगी। भारत सरकार की सख्त आपत्ति को देखते हुए भले ही मेटा ने माफी मांग ली हो, लेकिन मार्क भरोसे के लायक नहीं हैं। यह माफी जहां जरूरी थी वही अब स्वागतयोग्य भी है। लेकिन मार्क का भारत के प्रति नजरिया गैर जिम्मेदाराना, लापरवाहीपूर्ण एवं दोषपूर्ण है। ऐसी निरंकुश सोच एवं उच्छ्वस्त भावनाएँ बाली इमारत खोखली एवं विनाशकारी ही होती हैं।

यह वाकई हैरत की बात है कि जुकरबर्ग ने भारत को भी उन देशों में शामिल कर लिया जहां पिछले साल चुनाव में सरकारों ने सत्ता गंवाई। तथ्य यह है कि भाजपा की सीटें भले कम हुई हों, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने बहुमत हासिल कर सरकार में वापसी की एवं सफलतापूर्वक सरकार को चला रही है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और न केवल देश में बल्कि दुनिया में भारत का परचम फहरा रहे हैं। इस तथ्य से जकरबर्ग कैसे अनजान हो सकते हैं? क्या वह जानबूझकर भारत सरकार के बारे में गलत

मेटा प्रमुख मार्क के भारक एवं गुरमाह करने वाले बयान र केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रतिक्रिया दी और इसे लत जानकारी करार देते हुए तथ्य और विश्वसनीयता बनाए बने का आह्वान किया। मेटा के पब्लिक पार्लिसी के वाइस सिडेंट, शिवनाथ ठुकराल ने अश्विनी वैष्णव के पोस्ट पर बाब देते हुए लिखा, मार्क जुकरबर्ग का यह कहना कि 2024 के चुनावों में कई देशों में सत्ताधारी पार्टियां फिर से नहीं नी गईं, कई देशों के लिए सही है, लेकिन भारत के लिए हीं। हम इस अनजाने में हुई गलती के लिए माफी मांगते हैं। भारत मेटा के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश है और हम इसके नियोगेशन से भरे भविष्य का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित। भारत को अपना बाजार मानने वाले मेटा के लिये ऐसी ल अनायास या जानबूझकर जैसे भी हो, होना दुर्भाग्यपूर्ण है। योंकि भारत जैसे सशक्त एवं ताकतवर लोकतांत्रिक दैश के नये गलत जानकारी प्रसारित करना देश की छवि को धूमिल रती है। यह तो भारत की उदारता, सहिष्णुता एवं लमनसाहत है कि उसने ऐसी अक्षम्य गलती पर भी माफी संतोष कर लिया, वरना भारी जुर्माना या अन्य कठोर सजा प्रवधान हो सकते थे। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों इस्तेमाल सिर्फ अधिक से अधिक मुनाफा हासिल करने मकसद से हो रहा है। लेकिन इसके लिये समाज को कसान पहुंचाना कैसे जायज हो सकता है? इस तरह की गैर मपेदारी एवं लापरवाही खतरनाक हो सकती है और इसकी जाज नहीं दी जा सकती। ताजा विवाद को सरकार ने भीरता से लिया है, यह अच्छी बात है। लेकिन जरूरी है कि विंता इसी मामले तक सीमित न रहे। हेट स्पीच, तथ्यों को रोडमरोड कर प्रस्तुत करना और फेक न्यूज के ऐसे अन्य मामले भी राशीय एकता एवं राष्ट्र के अस्तित्व एवं अस्मिता के नये गंभीर एवं चुनातीपूर्ण हैं। सरकार की सख्ती जहां मेटा ज्यादा जिम्मेदार बनाये वहीं अन्य मंचों के लिये भी सबके ने।

माफी के बाद ज़ुकरबर्ग जैसे मालिकों को भी यह निश्चित होगा कि उनके अधीन चलने वाले सोशल मीडिया चंचों पर भारत के प्रति किसी झूठ, भ्रम एवं असत्य बयानी न सिक्का न चले। क्योंकि भारत की उदारता को उसकी मजोरी मानने की मानसिकता घाटक हो सकती है। भारत ने लेकर कोई गलत सूचना संचारित-प्रसारित न हो, तथ्यों पर प्रामाणिकता एवं सच्चाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नगढ़त या झूठी सूचनाओं का प्रचार- संचार अब भारत के तरे सहनीय नहीं है। फेसबुक या अन्य सोशल मंचों पर बहुत री झूठी, भ्रामक, विध्वंसक या फर्जी सूचनाएं समय-समय र धूमती रहती हैं, जिससे भारत की राष्ट्रीय एकता, अप्रदायिक सौहार्द, इंसानी सद्व्यवहाना आहत होती रही है। भारत के कतिपय राजनीतिक दल इसके लिये ऐसे मंचों को अत्साहन भी देते हैं लेकिन इन सब स्थितियों के बावजूद भारत को मजबूती से इनके खिलाफ खड़े होकर उनको उनकी मैन दिखाना ही चाहिए। ऐसी सख्ती ही भारत की छवि को जबूती प्रदान करेंगी एवं तभी दुबारा ऐसा दुस्साहस करने की ओई चेष्टा नहीं करेगा।

# सत्ता की बैसाखी पर टिके होने से बदल जाते हैं नेताओं के सुर

का इस्तेमाल ने छात्रों और उनके संगठनों के आक्रोश को और बढ़ा दिया।

बिहार का तरह राजस्थान भी कांग्रेस शासन के दौरान पेपर लीक प्रकरणों के कारण सुर्खियों में रहा है। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुई प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आए। सब इंस्पेक्टर भर्ती, सीएचओ भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती सहित कई परीक्षाओं के पेपर लीक होने के खुलासे हुए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से व्याख्याता भर्ती 2022 की परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया। पेपर लीक मामले में उलझी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर प्रदेश के लाखों युवाओं में हर ताजा अपडेट का इंतजार है। पेपर लीक और डम्पी अभ्यर्थियों के जरिए सैंकड़ों युवाओं ने नौकरी हासिल कर ली थी। इस मामले की जांच करने वाली एसओजी ने भी व्यापक स्तर पर पेपर लीक होना माना और इस परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश पुलिस मुख्यालय को भेजी थी। पुलिस मुख्यालय और मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने भी दर्शकों द्वारा दर्शकों द्वारा दिया गया दर्शकों द्वारा दिया गया

परीक्षा का रद्द करने का सफारी का, लाकन सरकार ने इस भर्ती परीक्षा को अभी तक रद्द नहीं किया। राज्य सरकार ने एसआई भर्ती 2021 में चयनित सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों के आगामी प्रशिक्षण पर रोक लगा दी। सरकार ने यह निर्णय राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश के बाद लिया। एक साल की लंबी एक्सरसाइज में अभी तक 50 सब इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं। आरपीएससी के सदस्य पकड़े गए। आश्वर्य की बात यह है कि राजस्थान में भाजपा सरकार केही एक केबीनेट मंत्री अपनी ही सरकार के



फैसलों पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठा रहे हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सत्तारुढ़ भाजपा अभी तक इस पर कोई ऐलान नहीं कर पायी।

अनुशासित माने जानी वाली भाजपा की मजबूरी है कि मीणा के खिलाफ पार्टी और सरकार की लाइन से अलग हट कर चलने को लेकर कार्रवाई नहीं कर सकती। इसमें भाजपा को मीणा के साथ जुड़े मीणा वोट बैंक के खिसकने का डर है। सत्ता के लिए राजनीतिक दल किस हद तक उसूलों को ताक पर रख देते हैं, मीणा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना इसका उदाहरण है। मीणा मंत्री पद से इस्तीफा तक दे चुके हैं, हालांकि उन्होंने इस्तीफा लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन पर

अपनी जिम्मेदारी मानते हुए दिया था। पार्टी ने अनुसूचित जाति में कोई गलत संदेश नहीं जाए। इसलिए मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। बैंक के लिए समझौते की ऐसी अनोखी मिसाल देश में शायद ही कहीं देखने को मिले, जहाँ एक नेता के मंत्रीपद से इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि उसकी पार्टी विरोधी कार्रवाई झेलने को भी पार्टी मजबूर है। दरअसल ऐसे सार्वजनिक विवादित मुद्दों पर किसी भी सरकार वे लिए फैसला लेना आसान नहीं होता। सरकारें एवं तरफ जहाँ रोजगार देने के लिए अपनी छवि सुधारना में लगी होती हैं, वहाँ दूसरी तरफ फिर से परीक्षण करवाने की कवायद खर्चीली और देरी करने वाले होती है। राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी के सामने समस्या यह भी होती है कि पेपर लीक होने से चुनिंदा लोग







